एक दशक की बैलेंस शीट!

रिपोर्ट कार्ड 2014-24

सरकारी संपदो की मुद्रीकरण

लोकतंत्र का सार यह है कि हम सरकारों को उनके दावों और वादों के हिसाब से जवाबदेह बनाएं। लेकिन हाल के वर्षों की सबसे बड़ी क्षति जवाबदेही का विचार रही है। मीडिया में विभाजनकारी और अंधराष्ट्रवादी अतिशयोक्ति सामूहिक भूलने की बीमारी को बढ़ावा देती है। यह रिपोर्ट कार्ड (हालांकि निर्णायक नहीं) वित्तीय जवाबदेही नेटवर्क इंडिया की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो वित्तीय और आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन के कुछ दावों और वास्तविकता पर नज़र डालने और उजागर करने का प्रयास करता है।

फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया - फैन इंडिया

दावे

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) 2021 का दावा हैकि 2022-25 की अवधि मेंसार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण करके 6 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

एनएमपी से जुटाए गए राजस्व से बुनियादी ढांचे का विकास होगा और इसका इस्तेमाल नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में किया जाएगा।

केवल घाटे में चलने वाली संपत्तियाँ या ऐसी संपत्तियाँजिनसे उचित रिटर्न नहींमिला है, का मुद्रीकरण किया जाएगा।

वास्तविकता

क्या यह वाकई पट्टा (लीज) है

एक 25 वर्षीय संपत्ति स्थानांतरण संपत्ति को पूरी तरह से बेचने के समान है। लाभ-प्रेरित निजी कॉरपोरेशन केवल सार्वजनिक संपत्ति किराया देने और फिर भविष्य में सरकार को उन्हें वापस देने में दिलचस्प नहीं होंगे। जिन सम्पत्तियों का मुद्रीकरण किया गया है, उनमें लंबी अवधि के अनुबंध हैं जो समाप्त होने के बाद उनकी इच्छानुसार पुनर्नवीकरण हो सकता है, यहां तक कि असामान्य समय के लिए प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को संपत्ति पर नियंत्रण स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाता है।

संपत्तियों का अवमूल्यन:

ऐसे कोई स्पष्ट दिशानिर्देश या ढाँचे नहीं हैं जिनके द्वारा संपत्तियों के मूल्य की गणना की जाती है। विभिन्न संपत्तियों के लिए अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसकी कोई न्यूनतम सीमा या अनुमानित मूल्य का कोई हिस्सा नहीं है जिसके लिए संपत्ति बेची जानी है। इसलिए, संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेचा जा सकता है। पट्टे की अवधि या संपत्तियों को पट्टे पर देने वाले प्राइवेट प्लेयर्स की अपेक्षित कमाई के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।

26,700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें (कुल NHAI सड़कों का 22%) का मुद्रीकरण किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इससे उसे 1.6 लाख करोड़ रुपये की कमाई होगी। यह संपत्ति का अत्यधिक कम मूल्यांकन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2019 में लगाए गए अनुमान के आधार पर, 26,700 किमी चार-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्माण लागत 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

मुद्रीकरण के लिए 26,642 करोड़ रुपये की राशि से 8,154 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनें निर्धारित की गई हैं। यह सभी मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का लगभग आधा है। 8,154 किलोमीटर पाइपलाइन के निर्माण की लागत लगभग रु. 48,924 करोड़ हैं। पाइपलाइनें निजी खिलाड़ियों को उनकी लागत से लगभग आधी कीमत (54%) पर बेची जा रही हैं।

जबकि भाजपा सरकार ने दावा किया है कि केवल घाटे में चल रही संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा, सेल, गेल, ओएनजीसी और कई अन्य लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियों को मुद्रीकरण के लिए रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

कैसे यह सामान्य लोगों के पर्स को नुकसान पहुंचाएगा?

दिनांक 8 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एक सवाल का उत्तर के अनुसार, सरकार का लक्ष्य देशभर में **400 रेलवे स्टेशनों का मुद्रीकरण** करना है। इससे यात्रियों के लिए और रेलवे के लिए लागतों में बढ़ोतरी होगी।

भारत जैसे देश में जहां गरीबी का स्तर ऊंचा है और बाजार खंडित हैं, जहां बड़ी संख्या में वंचित परिवारों को अभी भी जीवन की बुनियादी जरूरतों तक पहुंच नहीं मिल पाई है, निजी एंटरप्राइज जो बड़े पैमाने पर लाभ पर आधारित है, उससे इन सेवाओं को वाजिब कीमत पर प्रदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

सरकार मुद्रीकरण से 6 लाख करोड़ जुटाने का दावा कर रही है. इसलिए निजी कंपनियाँ कम से कम यह राशि जल्द से जल्द जुटाना चाहेंगी जो वे पहले ही सरकार को चुका चुकी हैं और फिर वे मुनाफे और ब्याज का भी हिसाब देंगी। सीमित समय सीमा में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, निवेशक अनुमानित रूप से कीमतें बढ़ाएंगे, प्रतिस्पर्धा को सीमित करेंगे या रखरखाव में कटौती करेंगे। इसका अनिवार्य रूप से अनुवाद लोगों, उपभोक्ताओं पर उच्च और अत्यधिक उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में बोझ और संपत्तियों के रखरखाव में गिरावट के रूप में होगा।

दुनिया भर में उदाहरण:

इस तरह का सबसे कुख्यात **मामला बोलीविया में बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों का मुद्रीकरण** था। इतना कि उन्होंने नदी से भी पैसा कमाना शुरू कर दिया और निजी कंपनी ने जल शुल्क बढ़ा दिया, जिससे पानी का बिल लगभग आठ गुना बढ़ गया। इसके कारण कोचाबम्बा में विरोध प्रदर्शन हुआ क्योंकि जनाक्रोश के परिणामस्वरूप अंततः शासन परिवर्तन हुआ। इसलिए इस तरह के मुद्रीकरण का नतीजा बिल्कुल स्पष्ट है। लोगों को ऐसे कदमों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

एक और **उदाहरण जिससे हम सबक ले सकते हैं वह है न्यू साउथ वेल्स (ऑस्ट्रेलिया) में खंभों और तारों के निजीकरण** का नतीजा, जहां निजीकरण के पांच साल बाद बिजली की कीमतें दोगुनी हो गईं। इतना कि 2017 में सरकार को अनावश्यक खुदरा विक्रेता शुल्क हटाकर और छूट बढ़ाकर एनएसडब्ल्यू परिवारों और छोटे व्यवसायों को बचाने के लिए ऊर्जा सामर्थ्य पैकेज के साथ कदम उठाना पड़ा।

सिंगापुर में रेल परिवहन सबक लेने लायक एक और उदाहरण है। 2011 और 2017 के बीच मास रेल ट्रांसपोर्ट का प्रदर्शन निजी हाथों के तहत कई हाई-प्रोफाइल रेल व्यवधानों के कारण बाधित हुआ, जिसके कारण व्यापक सार्वजनिक आलोचना हुई। अंततः सिंगापुर सरकार को परिचालन परिसंपत्तियों पर नियंत्रण लेने, अपनी उपनगरीय ट्रेनों और सिग्नलिंग प्रणालियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कदम उठाना पड़ा क्योंकि मुख्य निजी ऑपरेटर ने रखरखाव में बहुत कम निवेश किया था जिसके कारण बार-बार खराबी आ रही थी जिससे यात्री फंसे हुए थे और नाराज थे।.

यदि हम वैश्विक अनुभव से सीखते हैं, तो ऐसे कदम उन्हें बेहद विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे **यूनाइटेड किंगडम या अर्जेंटीना में ट्रेन का किराए उड़ान की लागत को पार कर गई है और कंपनियों के अराजक निर्णयों ने ट्रेन की कुशलता को प्रभावित** किया। पुनः, यूनाइटेड किंगडम में रेलट्रैक, जो सिग्नलिंग ट्रैक और स्टेशन का प्रभारी कंपनी है, उदाहरण के लिए, अक्सर अपने लाभ को रेलवे की बुनियादी ढांचे में पुनवेष्टन नहीं करती थी, जिससे ट्रैक का गिरावट और दुर्घटनाएं होती थीं। आखिरकार, जनसंदेह सरकार को वहां पर दाखिल करने पर मजबूर कर दिया।

मु द्री क र ण
किस कीमत पर?

कई मामलों में निजी निगम स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करके मुद्रीकृत संपत्तियों का वित्तपोषण करेंगे। मूलतः वे नागरिकों के धन का उपयोग उन संपत्तियों पर नियंत्रण लेने के लिए करेंगे जो सबसे पहले नागरिकों के करों का उपयोग करके बनाई गई थीं! **अति-विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के हित के लिए सार्वजनिक हित को छोड़ दिया जाएगा**।

निकट अतीत के कड़वे अनुभवों के कारण आलोचक निजी उधारी को लेकर आशंकित रहे हैं। 2005-2011 की तेजी अवधि के बाद, **बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए पैसा उधार लेने वाली कई कंपनियां गहरे संकट में थीं,** जिसके कारण सार्वजनिक बैंक भारी एनपीए से जूझ रहे थे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे दोहराया नहीं जाएगा।

लाभ से प्रेरित निजी खिलाड़ियों द्वारा मुद्रीकृत उद्योगों और उद्यमों में आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों के हजारों श्रमिक काम तक पहुंचने का अपना अधिकार खो देंगे। मुद्रीकरण के लिए निर्धारित सबसे बड़ा ब्लॉक (52%) रेलवे (25%) और सड़कें (27%) हैं। हालांकि यह भेदभाव से भरा हुआ है, फिर भी रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है जहां दशकों से दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों को हितधारकों के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है, तमोघना हलदर लिखती हैं। 2020 के आंकड़े बताते हैं कि रेलवे में लगभग 25% कर्मचारी SC/ST पृष्ठभूमि से आते हैं।

आज की आर्थिक परिस्थितियों में निजी क्षेत्र के कितने लोगों के पास वास्तव में ऐसी पूंजी गहन परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने का साधन होगा? वह भी ऐसे समय में जब वे अपने स्वयं के व्यवसाय में निवेश भी नहीं कर रहे हैं। पर्याप्त बोलियाँ नहीं होंगी, **लेकिन हाँ, अनुकूल कीमतों और मूल्यांकन पर अनुकूल बोलियाँ होंगी! यह एकाधिकार बनाने का रास्ता है।**

प्रोफेसर चिराश्री दासगुप्ता का कहना है कि **ऐसी आशंकाएं हैं कि उदाहरण के लिए, भूमि का उपयोग रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, जिसके पारिस्थितिक और आर्थिक दोनों प्रभाव** हैं। यह आशंका प्रबल है क्योंकि शहरी रियल एस्टेट उन बारह क्षेत्रों में से एक है जिन्हें विशेष रूप से एनएमपी में शामिल किया गया है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने 18,200 करोड़ रुपये की बीएसएनएल संपत्ति और 5158 करोड़ रुपये की एमटीएनएल संपत्तियों के मुद्रीकरण को मंजूरी दी थी। वास्तव में बीएसएनएल और एमटीएनएल को केवल 550 करोड़ रुपये की जमीन का मुद्रीकरण करने के प्रबंधन के लिए आलोचना की जा रही है और सरकार ने उनसे देरी के बारे में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इससे एक बार फिर सरकारी जमीन को रियल एस्टेट उद्देश्यों के लिए बांटे जाने की आशंका पैदा हो गई है। एमटीएनएल और बीएसएनएल ने राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों से अनुमति की कमी और स्वामित्व के मुद्दों को देरी का कारण बताया है।

प्रो. दासगुप्ता यह भी बताते हैं कि एनएमपी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान (एनआईपी) को सह-टर्मिनस बना दिया गया है। उदाहरण के लिए, 2023-24 के बजट में एनआईपी के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के आवंटन की घोषणा की गई थी। **यह एक साल का आवंटन 6 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों से बहुत बड़ा है जो एनएमपी के तहत चार वर्षों में बनाई जानी थीं। क्या इसका भी कोई मतलब बनता है?**

सरकार ने FY23 के दौरान ₹1.6 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹26,000 करोड़ की संपत्ति का मुद्रीकरण किया था। इससे FY22 और FY23 में प्राप्त कुल मुद्रीकरण मूल्य ₹1.14 लाख करोड़ हो जाता है जो ₹6 लाख करोड़ के लक्ष्य का केवल 19% है। प्रो. दासगुप्ता को आशंका है कि यह देखते हुए कि मुद्रीकरण लक्ष्य मुश्किल से ही हासिल किए जा रहे हैं, सवाल उठता है कि फिर एनआईएफ के लिए घोषित भारी आंकड़ों को कैसे वित्तपोषित किया जाएगा? अब तक का स्पष्ट मार्ग महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश को कम करना रहा है। इससे असमानता और विषमता और बढ़ती है।

लार्सन एंड टुब्रो जैसे बुनियादी ढांचे के बड़े कॉर्पोरेट खिलाड़ियों ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें एनएमपी के तहत बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने भी एनएमपी में निष्पादन संबंधी मुद्दों पर अपनी आपत्तियां रखी थीं। **बड़ी पूंजी में उत्साह की कमी को अर्थव्यवस्था में भारी मांग की कमी से समझाया गया है। इस परिदृश्य को देखते हुए, बड़ी पूंजी सस्ते में पेशकश किए जाने पर भी संपत्ति हासिल करने में दिलचस्पी नहीं रखती है।**

अन्य रिपोर्ट कार्ड के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें या ऊपर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें:
https://bit.ly/BSofadecade

https://www.fanindia.net @_FANIndia Financial Accountability Network
Financial Accountability Network India - FAN India fanindia.info@gmail.com